Chief Minister's Information System
Budget Announcements 2016-17

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
1	209.0.0(2016-2017) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत चार वर्षों में 21 हजार गाँवों में जल संरक्षण का कार्य करवाया जाकर पेयजल का स्थायी समाधान किया जायेगा। जनवरी, 2016 तक इस अभियान के तहत 3 हजार 318 गाँवों में कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में इस अभियान हेतु 440 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत चार वर्षों में 21 हजार गाँवों में जल संरक्षण का कार्य करवाया जाकर पेयजल का स्थायी समाधान किया जायेगा। प्रथम फेज में अभियान अन्तडर्गत राज्य की समस्त 295 पंचायत समितियों में 3529 गांवों का चयन कर 27 जनवरी, 2016 से कार्यप्रारंभ किया गया है। इन गावों में स्वीकृत 96709 कार्यो में से 95192 कार्य पूर्ण किये गये है। वित्त विभाग द्वारा प्रावधान संशोधित कर 392.08 करोड एवं वॉटरसेस के 150.52 करोड का अतिरिक्त प्रावधान किया गया, जिसमें से 382.48 करोड का व्यय किये जा कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	Implemented
2	210.0.0(2016-2017) पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एवं पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ई-पंचायत व्यवस्था लागू की जायेगी, जिससे सम्पूर्ण सूचनाएं public domain पर उपलब्ध हो सकेंगी।	ईंटिग्रेटेड राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रत्येक जिला परिषद, पंचायत समिति एवं प्रत्येक पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत में पायलट आधार पर लागू किया जा चुका है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर (जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत) से अब तक कुल 447.00 करोड से अधिक का ऑन लाईन भुगतान किया जा चुका है। विभागीय पत्र दिनांक 23.01.2018 के द्वारा जिलों को यह निर्देश दिये गये है कि वर्तमान में सॉफ्टवेयर से जुडी हुई पंचायतों के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायत इस सॉफ्टवेयर से राशि भुगतान की कार्यवाही नहीं करें। यदि कोई पंचायत समिति की नवीन ग्राम पंचायत सॉफ्टवेयर से राशि का भुगतान करना चाहती है तो मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करके की जावें।	Task Started, but not Completed

Chief Minister's Information System

Budget Announcements 2016-17

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
3	211.0.0(2016-2017) नवगठित 47 पंचायत समितियों को वाहन, कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।	घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में वित्त विभाग द्वारा राशि रिलीज किये जाने की सहमति पश्चात दिनांक 05.05.2016 को अधिनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन की कार्यवाही की जा चुकी है।	Implemented
4	212.0.0 (2016-2017) आज जब पंचायतीराज संस्थाओं को पहले से कहीं अधिक धनराशि विकास कार्यों के लिए मिल रही है तो हमें इस राशि का उपयोग गाँवों अथवा पंचायतों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए करना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं यथा-राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, महात्मा गाँधी नरेगा, MLA LAD, MP LAD] जलग्रहण विकास, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आदि से प्राप्त राशि का समग्र मूल्यांकन हो और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत अपनी वार्षिक योजना ऐसे बनायें, जिससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली राशि का convergence कर गाँव के समग्र विकास संभव हो सके। इसी परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए, मैं निम्न नवीन योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ-	-	Action Not Required
5	213.0.0(2016-2017) 15 हजार से अधिक आबादी वाली समस्त ऐसी पंचायतें जो अपने स्वयं के संसाधनों से अग्निशमन वाहनों का संचालन एवं रखरखाव करने के लिए इच्छुक हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।	उक्त बजट धोषणा मा0 मुख्योमंत्री महोदया के अनुमोदन उपरांत ड्रॉप की जा चुकी है।	Not Feasible

Chief Minister's Information System

Budget Announcements 2016-17

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
6	214.0.0(2016-2017) राज्य की सभी पंचायत मुख्यालयों पर नियत दिवस को पंचायत शिविर का आयोजन कर ग्रामीण जनता के पंचायत स्तर पर विचाराधीन कार्यों का निस्तारण किया जायेगा। इन शिविरों में आवासीय पट्टों का आवंटन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जारी करने, पेंशन संबंधी कार्य एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित अन्य कार्य मौके पर ही सम्पादित किये जा सकेंगे।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ किये गये जिसमें ग्रामीण जनता को आवासीय पट्टों का आवंटन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जारी करने, पेंशन संबंधी कार्य एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित 17 विभागों के विभिन्न कार्य किये जा रहे है। राज्य की 295 पंचायत समितियों की समस्त 9890 ग्राम पंचायतों में यह शिविर आयोजित किये जा चुके है।	Implemented
7	6.0.0 (2016-2017) राज्य के सर्वांगीण विकास एवं नवनिर्माण के लिए टीम राजस्थान किस तरह समर्पित होकर कार्य कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के संसाधन जुटाने के लिए सांसद, विधायक, पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया, आमजन एवं civil societies का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए बाड़मेर के बुडीवाडा गाँव के हर परिवार ने इस योजना के लिए श्रमदान, टैक्टर, जेसीबी या धनराशि आदि में से किसी एक माध्यम से अपना योगदान देने का निश्चय किया है। राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए किये गये इस प्रयास की एवं इस तरह के अन्य	-	Action Not Required

Chief Minister's Information System

Budget Announcements 2016-17

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
	प्रयासों की जितनी सराहना की जाये, कम है। इस योजना के लागू होने के पूर्व से ही, ऐसा सहयोग मिलना राज्य की प्रगति के लिए एक healthy indicator है। यह अभियान जनक्रांति का रूप ले चुका है। इस योजना के लिए मिल रहे जन-सहयोग से हम सब बहुत उत्साहित हैं, तथा मैं इस अभियान से जुडे सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करती हूँ।		